

अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति (आईएमएफसी) में वक्तव्य *

दुव्वुरी सुब्बाराव

1. हमारे सबसे खराब भय को गलत साबित करते हुए, हाल में कुछ महीने पहले, जब हम इस्तानबुल में मिले थे, तब हमारे द्वारा की गई प्रत्याशा की तुलना में वैश्विक अर्थव्यवस्था का कायापलट बहुत तेजी से हुआ है। वर्ष 2009 की प्रथम तिमाही और इसकी पूर्ववर्ती तिमाही में तीव्र गिरावट के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था ने तीन तिमाहियों में धनात्मक वृद्धि दर्ज की है। हालांकि विभिन्न देशों में हुए सुधारों की गति में पर्याप्त भिन्नता है जिनमें उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं आगे रही हैं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था

2. हालांकि वैश्विक संभावना कुछ महीने पहले की तुलना में अधिक आश्वस्त लगती है, लेकिन वैश्विक मंदी से उभरने के रूप और गति के बारे में अनिश्चितता बनी हुई है। जहां बृहत-आर्थिक जोखिम कम हुआ है, वहीं असुरक्षितता जारी है। सॉवरिन जोखिम रूपरेखा में अवनति के बारे में चिंता बढ़ रही है और कुछ देशों में वित्तीय स्थिरता को खतरा दिखाई दे रहा है। प्रायः यह कहा जाता है कि हरेक वित्तीय संकट के बाद सॉवरिन ऋण संकट आता है, ऐसा अर्थव्यवस्था के प्रभावित हिस्से को सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा सहायता प्रदान करने के कारण होता है। क्या इस बार यह अलग होगा? हाल की घटनाओं ने राजकोषीय घाटों के लिए बाह्य वित्तपोषण प्रदान करने के क्रमिकतावादी दृष्टिकोण के गुण दिखाई दिये हैं। संकट और संकट-पश्चात् का अनुभव कुछ पुनर्विचार का अग्रदूत होना चाहिए कि बाह्य वित्तपोषण के लिए ऋण बाजारों को कैसे और कितना खोला जाये।

3. संकट के दौरान अस्थिर पूंजी प्रवाह मुख्य मुद्दा बना रहा है और अब भी ऐसा बना हुआ है क्योंकि संकट कम हो रहा है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) ने संकट के दौरान वैश्विक ऋण संकुचन के परिणामस्वरूप पूंजी प्रवाह को अचानक बंद होते और उलटा प्रवाह होते

* 24 अप्रैल 2010 को वाशिंगटन डी.सी. में अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति में भारतीय शिष्टमंडल के आईएमएफसी प्रमुख के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव का वक्तव्य।

(भारत के माननीय वित्त मंत्री और निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका शामिल हैं, का प्रतिनिधित्व करते हुए आईएमएफसी के सदस्य के रूप में)

देखा। अब प्रवृत्ति एक बार फिर उलटी हो गई है और कई ईएमआई वैश्विक प्रणाली में चलनिधि प्लावित होने, 'विस्तारित अवधि' में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कम ब्याज दरों के आश्वासन और ईएमई में विकास के वादे के परिणामस्वरूप निवल अंतर्वाह देख रहे हैं। पूंजी प्रवाह वित्तीय स्थिरता को भी संभाव्य रूप से कमजोर कर सकता है। सुविदित प्रश्न यह है कि ईएमई अस्थिर पूंजी प्रवाहों से लाभों को अधिकतम और लागतों को न्यूनतम कैसे करें, क्योंकि यह प्रवाह नीतिगत कार्यसूची में बाधा डालने के लिए लौट आया है।

4. हाल का संकट पूंजी नियंत्रणों के संबंध में विश्व की दृष्टिकोण में स्पष्ट रूप से बड़ा मोड़ लाया है। संकट ने सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी खाते को खोलने की सीमा और संकट के प्रतिकूल प्रभाव के बीच मोटे तौर पर सह-संबंध को देखा। निश्चित रूप से इसे पूंजी खाते को खोलने की समाप्ति के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि इस मत के शक्तिशाली प्रदर्शन के रूप में देखा जाना चाहिए कि अर्थव्यवस्थाओं को समय-पूर्व खोलने पर सहायता मिलने की बजाय चोट पहुंचाती हैं। उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने फरवरी 2010 में एक नीति संबंधी नोट प्रकाशित किया है जो इसकी दीर्घकालिक प्रामाणिकता को उलटा करता है। नोट में कुछ ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनमें पूंजी प्रवाह के उमड़ने पर पूंजी नियंत्रण नीतिगत प्रतिक्रिया का वैध घटक हो सकता है। चूंकि अब यह मोटी सहमति है कि नियंत्रण पूंजी प्रवाह के प्रबंध में 'वांछनीय और प्रभावी' हो सकते हैं, आईएमएफ और अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों को 'किस प्रकार के नियंत्रण और किन परिस्थितियों में नियंत्रण' करने के बारे में अध्ययन करने के लिए अनुसंधान करना चाहिए, ताकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं को नीति निर्माण के बारे में उपयोगी दिशानिर्देश मिल सकें।

कोष का अधिदेश

5. कोष ने संकट के प्रबंध के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। संकट से सीख लेते हुए कोष को संकट-पश्चात् के परिदृश्य के अनुकूल होने की जरूरत है। हम कोष के अधिदेश की समीक्षा का स्वागत करते हैं जिससे इसे बृहत्-वित्तीय स्थिरता और सुव्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण देशों की नीतियों के बाहरी प्रभाव जैसे क्षेत्रों पर प्रभावी ढंग से पुनः ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलनी चाहिए। ऐसी समीक्षा से कोष की निगरानी और ऋण देने के साधनों में महत्वपूर्ण सुधार होना चाहिए।

6. कोष के निगरानी और ऋण देने के कार्य अलग-अलग हैं और उन्हें ऐसे ढंग से करने की जरूरत है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के हितों को बेहतरीन ढंग से पूरा कर सकें। संकट से प्रमुख सीख यह मिली कि प्रणालीगत जोखिम कम परिपक्व बाजारों में ही नहीं होता, बल्कि उन्नत देशों में भी होता है। निगरानी और ऋण देने के कार्यों के बीच अंतर की स्पष्ट रेखाएं यह सुनिश्चित करने के लिए बनाये रखी जायें कि कोष की अधिक गहन निगरानी न केवल उधारकर्ताओं और संभावित उधारकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करती हो, बल्कि लेनदार सदस्यों पर भी करती हो।

निगरानी

7. कोष की निगरानी कोष के वित्तपोषण कार्य के विपरीत असुरक्षितता पर ध्यान केंद्रित करने और संकट के प्रारंभ होने का पता लगाने की एहतियाती भूमिका है जो अनिवार्य रूप से संकट को कम करने की भूमिका अदा करती है। संकट की सीख ने ऐसे ढंग से सावधानीपूर्वक जांच करना आवश्यक बना दिया है जिसमें कोष अपनी, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय, दोनों निगरानी करता है।

8. निगरानी प्रभावी हो और यह आस्था एवं विश्वास जगाये, इसके लिए यह अनिवार्य है कि यह निष्पक्ष, सुस्पष्ट

और अपक्षपाती हो। इसे हम कैसे परिचालित कर सकते हैं? अधिदेश कार्यकारी बोर्ड के निर्णय, जो साधारण बहुमत से लिया गया था, से उत्पन्न हुआ है, वह बाद में भिन्न-भिन्न व्याख्याओं के लिए खुला हुआ, जिससे औचित्य का स्पष्ट त्याग हुआ। हमारी दृष्टि में इस उद्देश्य को हासिल करने का बेहतर तरीका है - कोष को अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली तथा सदस्यों द्वारा घरेलू नीतियों के संचालन के अंतर्गत वित्तीय क्षेत्र की नीतियों पर निगरानी सौंपने के लिए सहमति अंतर्नियमों में संशोधन करना।

9. हमें विश्वास है कि कोष अपनी सार्वभौमिक सदस्यता और समकक्ष समीक्षा के मंच, जो यह प्रदान करता है, के कारण प्रभावी बहुपक्षीय निगरानी करने के लिए रणनीतिक रूप से अवस्थित है। तदनुसार, हम पिछले जमा स्टॉक की रिपोर्टों, बहुपक्षीय परामर्श और क्षेत्रीय/देश समूहों के साथ विस्तारित परस्पर-क्रिया जैसे नवोन्मेषी लिखतों के जरिये बहुपक्षीय निगरानी में सुधार करने के लिए व्यापक सहमति बनाने हेतु रचनात्मक रूप से और खुले दिमाग से लग सकते हैं। वास्तविकता की जांच के लिए उनकी उपयोगिता के बारे में निर्णय लेने से पहले प्रायोगिक परीक्षण करना चाहिए।

10. द्विपक्षीय निगरानी कोष के अधिदेश का मुख्य कार्य है और बहुपक्षीय निगरानी में सुधार के प्रस्तावों को सुदृढ़ और निष्पक्ष द्विपक्षीय निगरानी के अनुसरण में समझौता नहीं करना चाहिए। आईएमएफ की द्विपक्षीय और बहुपक्षीय निगरानी के बीच सहक्रिया सुनिश्चित करने की जरूरत है। सामयिकता में सुधार और अधिक संप्रेषण वांछनीय है लेकिन रिपोर्टों के अनावश्यक प्रचुरोद्भाव से दूर रहने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है जिसमें संसाधनों को व्यापक रूप से थोड़े-थोड़े फैला कर निगरानी की गुणवत्ता के साथ समझौता किया जाता है।

11. वित्तीय क्षेत्र की निगरानी का मुद्दा असल में महत्वपूर्ण है। नये दृष्टिकोणों की क्षमता का निर्धारण करने में हमें खूबी नजर आती है। इस संबंध में वैश्विक वित्तीय नेटवर्कों को मापना, बड़ी जटिल वित्तीय मध्यवर्तियों (एलसीएफआई), आस्ति प्रबंधकों और केन्द्रीय प्रतिपक्षकारों (सीसीपी) के साथ गहन जुड़ाव, मानक निर्धारित करने वाले निकायों के साथ गहन और अधिक प्रभावी सहयोग, शीघ्र चेतावनी अभ्यास (ईडब्ल्यूई) के बारे में वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) के साथ जारी आबंध सहित, कुछ पहलकार्य हैं। संकट से सीख इस बात को रेखांकित करती है कि महत्वपूर्ण वित्तीय केन्द्रों और व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण देशों पर ध्यान और बढ़ाया जाये।

12. संकट से सीख के मद्देनजर बृहत्-प्रणालीगत जोखिमों का मूल्यांकन करने में वित्तीय क्षेत्र की निगरानी को मजबूत करने के पीछे तर्काधार है। हालांकि, इस भूमिका में परिचालन की रूपात्मकता में एक ओर मिशन के जरूरत से ज्यादा फैलने को रोकने और आईएमएफ की विशिष्ट भूमिका को बनाए रखने तथा दूसरी ओर एफएसबी एवं बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) की विशिष्ट भूमिका को बनाये रखने के लिए गहन विचार-विमर्श की जरूरत होगी। हमें इस स्तर पर अनिवार्य वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) की जरूरत और उपयोगिता के बारे में चिंता है। एफएसएपी को भावी संभावना वाली और संकेंद्रित बनाकर सबसे ज्यादा सहभागिता निश्चित करने के लिए बढ़े हुए प्रयासों के साथ एफएसएपी के स्वैच्छिक स्वरूप को बनाये रखना बेहतर है। उन देशों, जो ऐसा अभ्यास पहले ही कर चुके हैं, के लिए एफएसएपी की पुनरावृत्ति करने से पहले व्यवस्थित रूप से सभी महत्वपूर्ण देशों के लिए एफएसएपी का प्रथम राउंड करवाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

13. प्रभावी निगरानी की एक प्रमुख पूर्वपेक्षा अभिशासन में सुधार है जो बदलती वैश्विक आर्थिक वास्तविकताओं

को प्रदर्शित करता है और समानता एवं संतुलन सुनिश्चित करता है। प्रभावी कार्यान्वयन आगे के सुधारों के लिए व्यापक सहमति भी तैयार करेगा।

कोष की वित्तपोषण भूमिका

14. संकट ने सुदृढ़ नीतियों वाली अर्थव्यवस्थाओं और ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रभावित किया, जो इसके अधिकेद्र से दूर थीं, इसने वैश्विक वित्तीय सुरक्षा के आवरण को प्राथमिकता के आधार पर सुदृढ़ करने की जरूरत पर बल दिया। कोष को ऐसा सुरक्षा आवरण एक साथ करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। वैश्विक वित्तीय सुरक्षा आवरण का 'वैश्विक' होना जरूरी है और इसमें कई भागीदार शामिल हैं जैसे अलग-अलग देश, केंद्रीय बैंक, क्षेत्रीय व्यवस्थाएं, आईएमएफ और अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं सहित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं (आईएफआई)। कोष को अपना अत्यधिक विस्तार करने से सावधान रहते हुए ऐसी वैश्विक व्यवस्था का उत्प्रेरण करने की जरूरत है।

15. जहां एहतियाती लचीले लिखत संकट को रोकने में सहायता करेंगे, वहीं संकट ने हमें यह भी सिखाया है कि वित्तीय सुरक्षा आवरण का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व देशों द्वारा भंडार का संचयन करना है। विशेषकर ऐसे देशों को, जिनमें भंडार अंतर्निहित रूप से अस्थिर पूंजी प्रवाहों के लिए चालू खाते के घाटों के संदर्भ में बनाया गया है। ऐसे देशों को वैश्विक सुरक्षा आवरण में भागीदारों के रूप में समझा जाना चाहिए, जिसमें बहुदेशीय कार्यप्रणाली पूरक के रूप में कार्य करें, न कि राष्ट्रीय स्तर पर संचित भंडार के स्थानापन्न के रूप में।

16. कोष के ऋण देने के साधनों के प्रस्तावित विकासमूलक सुधार पर गुणों के आधार पर और कोष की सदस्यता के काफी बड़े खंड की संभावित उपयोगिता के आधार पर उचित विचार-विमर्श करना चाहिए। मौजूदा

और हाल में सृजित लिखतों में सुधार का प्रयास होना चाहिए और नये लिखतों की निवल संवृद्धि न्यूनतम रखी जानी चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण संभावित प्रयोक्ताओं और वित्तीय बाजारों, दोनों की नजरों में संकेतन प्रभाव और लिखतों का पूर्वानुमान बढ़ायेगा।

17. बहु-देशीय अदला-बदली व्यवस्था (एमएसएल) पर ध्यानपूर्वक विचार करना है जिसमें प्रणालीगत स्थिरता के हित में कोष सहायता का एकपक्षीय ऑफर प्रस्तावित है। लिखत में कोष से उधार लेने के लांछन को मिटाने का वचन होता है और ऐसे लिखत में सदस्यता के संभावित हित का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऐसे स्वरूप के लिखत से उत्पन्न संप्रेषण मुद्दे और बाजार संकेत इसके सॉवरिन सदस्यों की तुलना में कोष को अत्यधिक अधिकार प्रदान कर सकते हैं जिसे उचित प्रकार से संयमित करना होगा। अंतिम निर्णय लेने से पहले इस प्रस्ताव के गुणावगुणों पर चर्चा के लिए अधिक समय दिया जाना उचित होगा।

आईएमएफ के संसाधन

18. अप्रैल 2009 में लंदन सम्मेलन में कोष के संसाधनों को तिगुना करने की घोषणा ने जारी संकट से उत्पन्न अनिश्चितता को कम करने का कार्य किया। उस घोषणा की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में हम 600 बिलियन अमरीकी डॉलर उधार लेने की नई व्यवस्था के विस्तार का स्वागत करते हैं और सभी सदस्यों से बढ़े हुए स्तर की यथाशीघ्र अभिपुष्टि करने की अपील करते हैं। भारत सहित ऐसे देश जो परंपरागत लेनदार नहीं हैं, विस्तारित एनएबी में पर्याप्त अंशदान देने के लिए आगे आये हैं। इससे कोष के अभिशासन में और परिवर्तनों की जरूरत का संकेत मिल जाना चाहिए।

19. हमने कोष को हमेशा कोटा-आधारित संगठन बनाये रखने के महत्व का समर्थन किया है। इसका अर्थ यह है

कि कोटा-आधारित संसाधन और उधार संसाधन उचित अनुपात में होने चाहिए। हमने एनएबी में पर्याप्त वृद्धि करने के निर्णय का इस आधार पर समर्थन किया था कि चूंकि संसाधनों की तत्काल जरूरत है और कोटा बढ़ने में समय लगता है, अतः एनएबी संभाव्य कोटा वृद्धि के लिए अस्थायी सेतु का काम करेगा। हम इस स्तर पर कोष के उधार देने योग्य संसाधनों को और बढ़ाने की जरूरत नहीं समझते हैं। हम कोटा संसाधनों में पर्याप्त वृद्धि का समर्थन करते हैं ताकि कोटा में वृद्धि प्रभावित होने पर एनएबी को वापस किया जा सके। यह सुनिश्चित करेगा कि कोष कोटा-आधारित संगठन बना रहे, जो इसे रहना चाहिए।

अभिशासन में सुधार

20. अभिशासन में सुधार कोष के अधिदेश की वैधता और प्रभावशीलता का केन्द्रबिन्दु होगा। हम इस बात की प्रशंसा करते हैं कि प्रबंध निदेशक ने अपने कथन में इसको स्वीकार किया है। यदि आईएमएफ के अधिदेश के स्पष्टीकरण और पुनः संकेद्रण की वैधता है, तो इसे कोटा अंश सहित अभिशासन संरचना में परिवर्तन के बाद में करना चाहिए, न कि उससे पहले, जिसमें उन्नत लेकिन अभी भी गलत सूत्र के आधार की बजाय सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से मापित वर्तमान और उभरती वैश्विक आर्थिक वास्तविकताओं को प्रदर्शित करना चाहिए।

21. कोटा में वृद्धि का आकार कोष में कोटा अंशों के पुनर्व्यवस्थित महत्वपूर्ण अभिशासन मुद्दे से गहनता से संबद्ध है। कोटा में बड़ी वृद्धि न केवल अवसर प्रदान करती है, बल्कि उभरते बाजारों और विकासशील देशों (ईएमडीसी), जिनका सदस्यता में बड़ा हिस्सा है, की प्रत्याशाओं को पूरा करने के लिए कोटा के महत्वाकांक्षी पुनर्व्यवस्थापन की भी जरूरत है। उन्नत देशों से ईएमडीसी को कोटा अंश का ऐसा पर्याप्त हस्तांतरण

वर्तमान वैश्विक आर्थिक वास्तविकताओं को बेहतर प्रदर्शित कर सकेगा और कोष को उचित सिद्ध करेगा।

22. हम ईएमडीसी के पक्ष में समूह के रूप में कोटा अंशों का कम से कम 7 प्रतिशत हस्तांतरण की हमारी मांग दोहराते हैं। स्टाफ के प्रारंभिक प्रस्ताव प्रत्याशाओं से काफी कम हैं। हमें निराशा है कि कोष और इसके संसाधनों के अधिदेश के विस्तार के लिए प्रस्तावों में प्रदर्शित आकांक्षा कोटा अंशों की पुनर्व्यवस्था के प्रस्तावों की आकांक्षा से मेल नहीं खाती है।

23. उन्नत लेकिन अभी भी कोटा का गलत सूत्र वैश्विक आर्थिक वास्तविकताओं को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित नहीं करता। सूत्र की कमियां, जिसमें चरों के भार और परिभाषाएं शामिल हैं, का सभी को पता है और अप्रैल 2008 में कोष के गवर्नर मंडल ने यह निर्णय लिया कि सूत्र का पुनः प्रयोग करने से पहले मुद्दे को पुनः देखने की जरूरत है। अब तक का दृष्टिकोण इस पर 'कार्य करने' की बजाय मौजूदा सूत्र पर अधिक विश्वास करता है, अतः इसे कोष की वैधता बढ़ाने के रूप में नहीं देखा जा सकता। आदर्श सूत्र को पीपीपी-जीडीपी के लिए भार में अत्यधिक वृद्धि करने के साथ पुनः तैयार करने की मांग की गई है ताकि चालू आर्थिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रदर्शित किया जा सके।

24. विश्वसनीयता बनाये रखने के लिए जनवरी 2011 की अंतिम तारीख का पालना करना है। हम अधिक लंबे समय के ढाँचे के साथ सूत्र में संशोधन का कार्य साथ-साथ करने के लिए तैयार हैं। इस बीच, वर्तमान राउंड में कोटा आबंटन वैकल्पिक कार्यप्रणाली के आधार पर पूरा किया जा सकता है जो जटिल और टेढ़े-मेढ़े समायोजनों के बिना समरूप और पारदर्शिक आधार पर चलता है। इस दृष्टिकोण से वास्तविक न्यून-प्रतिनिधित्व का उपचार हो जाना चाहिए और इससे गतिशील ईएमडीसी को स्वतः पहचान मिलनी चाहिए।

25. हम सबसे गरीब देशों के मत शेयर के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह मूल मतों में वृद्धि की बजाय कोटा के आबंटन के जरिये अच्छे से किया जाता है जिसेक लिए नियमों में और संशोधन करने की जरूरत होगी और यह पूरी प्रक्रिया में देरी कर सकता है।

26. अभिशासन सुधार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र उल्लेखनीय एवं अर्थपूर्ण कोटा और ध्वनि सुधार है। अभिशासन सुधार के अन्य सभी पहलू इस सुधार के बाद और इसके अनुरूप होने चाहिए। आईएमएफ से संबद्ध मुद्दों में मंत्रियों का अधिक राजनीतिक जुड़ाव का निश्चित रूप से स्वागत है। इस स्थिति में ऐसा जुड़ाव आईएमएफसी की कार्यप्रणाली में सुधार के द्वारा अच्छे से प्राप्त किया जा सकता है। हम आईएमएफसी का सर्वसम्मति पर आधारित निकाय के रूप में सम्मान करते हैं और विश्वास करते हैं कि कोष की वैधता में वृद्धि आईएमएफसी की प्रभावशीलता में भी वृद्धि करेगी।

27. दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के बीच कार्यकारी बोर्ड के पदों का पुनर्वितरण भी एक प्राथमिकता है। प्रतिनिधित्वता और प्रभावशीलता के बीच उचित संतुलन बैठने की जरूरत है। इसमें उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व को प्रभावित किये बिना संभावित कटौती सहित बोर्ड के आकार में परिवर्तन शामिल हो सकता है। 85% की विशेष बहुसंख्यक सीमा निर्णयों को सर्वसम्मति के नजदीक लाती है और हमें कोष में मौजूदा मतदान बहुसंख्यकों में परिवर्तन का कोई बाध्यकारी कारण नज़र नहीं आता है।

निर्वाचन-क्षेत्र में प्रगति

28. अब मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में चर्चा करूंगा।

भारत

29. भारतीय अर्थव्यवस्था संकट के कारण विकास में आई कमी से तेजी से उभर रही है। वर्तमान अनुमान यह हैं कि हाल में समाप्त हुए राजकोषीय वर्ष 2009-10 के दौरान वास्तविक जीडीपी में 7.2% वृद्धि हुई, जो वर्ष 2008-09 के दौरान 6.7% से अधिक है। नीतिगत उद्देश्यों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने वास्तविक जीडीपी में वृद्धि की आधाररेखा अनुमान वर्ष 2010-11 के लिए 8.0% रखा था जिसमें और बढ़ोतरी की गुंजाइश रखी गई थी। वैश्विक वित्तीय संकट के मद्देनजर शुरू किये गये मौद्रिक और राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पहले संकट के संक्रमांक से प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में और इसके बाद यह सुनिश्चित करने में अर्थव्यवस्था तेजी से मंदी से उभरे।

30. हालांकि मुद्रास्फीति के मोरचे पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं वे चिंताजनक हैं। मुद्रास्फीति अब धीरे-धीरे सामान्य रूप लेती जा रही है जो पहले केवल आपूर्ति पक्ष के कारकों से संचालित होती थी। मुद्रास्फीति जोखिम को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रसरणशील मौद्रिक नीति से अंशांकित रूप से निकलना प्रारंभ किया। केन्द्रीय बजट 2010-11 में राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया गत वर्ष के दौरान राजस्व घाटा जीडीपी के 5.3% के घटाकर 4.0% और राजकोषीय घाटा 6.7% को घटाकर 5.5% कर, आरंभ की गई। आगे चलकर तीन प्रमुख अनिश्चितताएं मुद्रास्फीति के परिदृश्य को धुंधला कर देंगी। पहला, वर्ष 2010-11 में मानसून की संभावनाएं अभी स्पष्ट नहीं हैं। दूसरा, कच्चे तेल के मूल्य लगातार अस्थिर बने हुए हैं। तीसरा, मांग पक्ष की ओर से दबाव बनने के प्रमाण हैं। संतुलन के रूप में घरेलू मांग-आपूर्ति संतुलन और पण्यों के मूल्यों में वैश्विक प्रवृत्ति के मद्देनजर मार्च 2011 के लिए डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति की आधाररेखा का पूर्वानुमान 5.5% किया गया है। इस

पृष्ठभूमि में मौद्रिक नीति का संचालन मुद्रास्फीति के अवबोधन को 4.0%-4.5% के बीच की स्थिति में प्रतिबंधित और रोकना जारी रहेगा। यह मुद्रास्फीति के मध्यावधि उद्देश्य 3.0% के अनुरूप होगा, जो भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से व्यापक एकीकरण से सुसंगत है। इस संदर्भ में उन्नत देशों में समायोजनकारी मौद्रिक नीतियां, भारत में विकास की बेहतर संभावनाओं के साथ होकर देश में बड़ी मात्रा में पूंजी प्रवाह को प्रेरित कर सकती हैं। जहां भारतीय अर्थव्यवस्था की अवशोषी क्षमता बढ़ रही है, वहीं अत्यधिक प्रवाह विनिमय दर और मौद्रिक प्रबंध के लिए चुनौती बन सकता है।

श्रीलंका

31. श्रीलंका की अर्थव्यवस्था ने लचीलापन प्रदर्शित किया, जो चुनौतिपूर्ण घरेलू और बाह्य स्थितियों के बीच 2009 में 3.5% से बढ़ी। यह निष्पादन मुख्यतः 2009 की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था के मंदी से धीरे-धीरे उभरने के कारण हुई, जो अंतिम तिमाही में 6.2% की सुदृढ़ वृद्धि तक पहुंच गई। प्राधिकारियों के समन्वित और सामयिक नीतिगत कार्य घरेलू अर्थव्यवस्था के कायापलट में सहायक रहे, जिसके कारण चिरकालिक संघर्ष को समाप्त कर पाये। अर्थव्यवस्था में निवेशकों का बढ़ा हुआ विश्वास विदेशी वित्तीय प्रवाह में तेज बदलाव के रूप में प्रदर्शित हुआ, जिसके कारण भुगतान संतुलन (बीओपी) में 2.7 बिलियन अमरीकी डॉलर का अभूतपूर्व आधिक्य हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर 450% से अधिक बढ़कर 2009 के अंत तक 5.1 बिलियन अमरीकी डॉलर के उच्च ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। उल्लेखनीय उपलब्धि यह रही कि मुद्रास्फीति जून 2008 के 28.2% से तेजी से घटकर 2009 के अंत में 4.8% पर आ गई, यह गत दो वर्षों में अपनाये गये कठोर मौद्रिक नीतिगत उपायों और पण्यों के वैश्विक मूल्यों में उल्लेखनीय गिरावट का परिणाम है। कोलंबो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीसीपीआई) में वर्ष-

दर-वर्ष परिवर्तन द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति वर्ष 2009 में कम होकर औसत दर 3.4% रही, जो 1985 से अब तक सबसे कम है। सामयिक नीतिगत कार्यों ने वैश्विक वित्तीय संकट के संक्रामण और कुछ घरेलू वित्तीय संस्थाओं से संबद्ध कुछ संस्थाओं के असफल होने को सफलतापूर्वक कम किया गया। मजबूत विनियामक और पर्यवेक्षी ढाँचा एवं उन्नत जोखिम प्रबंध प्रणालियों ने बाहरी और घरेलू स्तर के सदमों को रोकने तथा वित्तीय प्रणाली में विश्वास कायम रखने के लिए वित्तीय प्रणाली को समर्थ बनाया। बदलते माहौल में वित्तीय संस्थाएं लाभप्रद बनी रहीं और उचित रूप से पूंजीकृत रहीं, हालांकि कठोर बाजार स्थितियों के कारण ऋण जोखिम बढ़ा। वर्ष 2009 में अनेक उपाय शुरू करने के बावजूद आर्थिक कार्यकलापों में मंदी और आयातों में कमी के कारण राजस्व में अत्यधिक कमी हुई। इसके अलावा, सरकारी खर्च में बढ़ोतरी संघर्ष के निर्णायक चरण के दौरान सुरक्षा से संबंधित अधिक व्यय और वर्ष की दूसरी छमाही से सतत तत्काल पुनर्वास, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण (आरआरआर) कार्यकलापों तथा साथ ही बढ़े हुए वेतन एवं मजदूरी, ब्याज भुगतान और सरकारी निवेश वाली जारी परियोजनाओं पर खर्च के कारण हुआ। तदनुसार, वर्ष 2009 में बजट घाटा 7.0% के संशोधित लक्ष्य की तुलना में बढ़कर जीडीपी का 9.8% हो गया, जिसके कारण उधारराशियों की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई। चिरकालिक आंतरिक संघर्ष की समाप्ति और शांति बहाली, समुचित नीतियों समर्थित आर्थिक समृद्धि और दीर्घकालिक व्यवहार्य विकास के लिए मजबूत आधार के प्रति अधिक आशावान बनाती है।

बांग्लादेश

32. बांग्लादेश में व्यापक आधार वाले सुधार हो रहे हैं जिनको बहु-गति वाली वैश्विक मंदी से उभरने और सुदृढ़ घरेलू मांग से बल मिल रहा है, इसमें कामगारों के लचीले प्रेषणों और राजकोषीय प्रोत्साहन से सहायता

मिली है। असल में बांग्लादेश बाहरी सदमों, विशेषकर हाल की वैश्विक मंदी के प्रतिकूल प्रभावों से पर्याप्त रूप से बचा रहा है। इन प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद इसकी बाह्य स्थिति विदेशी विनिमय के पर्याप्त भंडार और धनात्मक चालू खाता शेष के साथ सुदृढ़ बनी रही। वर्ष 2009-10 की दूसरी छमाही में विनिर्माण क्षेत्र सकारात्मक वृद्धि में लौट आया और औद्योगिक आयातों में बढ़ती प्रवृत्ति औद्योगिक कार्यकलापों में बढ़ती स्थिति का संकेत कर रही है। ऐसे भी प्रारंभिक संकेत हैं कि व्यापारिक माल के निर्यात में कमी न्यूनतम स्तर पर है और वस्त्र एवं परिधान से संबंधित आदेश बहियों का आकार काफी बढ़ रहा है जिनका हिस्सा कुल निर्यातों में तीन-चौथाई से अधिक है। जापान और चीन के निर्यात बाजारों की ओर बढ़ता भौगोलिक विशाखन उत्तरी अमेरिका और यूरोप के परंपरागत निर्यात बाजारों में घटती मांग को समायोजित कर रहा है। निर्माण कार्यकलापों में, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में तेजी है जो प्रेषणों और संपदा क्षेत्र के बढ़ते मूल्यों के कारण है। सेवा क्षेत्र के कार्यकलापों, विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य, खुदरा एवं खान-पान के कारोबार और वित्तीय सेवाओं में भी मजबूती आई है। वर्ष 2009-10 में कृषि उत्पादन की गति कमी हुई, जबकि इससे पहले वर्ष में 4.6% की अच्छी वृद्धि हुई थी। कृषि क्षेत्र में व्यापार की बेहतर शर्तें, निविष्टियों और ऋण की समय पर उपलब्धता से वर्ष 2010-11 में कृषि की संभावनाएं, मौसम की अप्रत्याशित प्रतिकूलताओं को छोड़कर, अच्छी होनी चाहिए। वर्ष 2009-10 में समग्र रूप से वास्तविक जीडीपी में वृद्धि 5.5-6.0% के बीच होने की संभावना है जिसमें ऊपर की ओर जाने की गुंजाइश है जबकि गत वर्ष यह 5.9% थी। इस प्रकार, लगभग एक दशक तक सुदृढ़ और स्थिर आर्थिक विकास होने की आशा है। उपभोक्ता मूल्यों के रूप में मुद्रास्फीति कम होने के पथ पर है जिसके 2009-10 के प्रारंभ के 6.6% से अक्टूबर 2009 के 5.1% की वापसी के संकेत

हैं हालांकि अंतरराष्ट्रीय खाद्य और गैर-खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि को प्रतिबिम्बित करते हुए हाल के महीनों में घरेलू मूल्यों में वृद्धि हो रही है जो जून 2010 तक लगभग 6.5% तक पहुंच सकती है। घरेलू मांग की स्थितियों के मजबूत बने रहने और निजी क्षेत्र के ऋण तथा आयातों में वृद्धि होने के साथ मौद्रिक एवं चलनिधि स्थितियां कठोर हो गई हैं। अंतर-बैंक मांग मुद्रा दरें अब 4% से अधिक हो गई हैं जो जुलाई 2009 में 1% से नीचे चली गई थीं। दूसरी ओर, बैंकिंग प्रणाली से सार्वजनिक क्षेत्र की उधारराशियां घट गई हैं, जो निजी क्षेत्र के बढ़ते कार्यकलापों के लिए संसाधन उपलब्ध करा रही हैं। उम्मीद है कि मौद्रिक नीति की अवस्थिति उदार बनी रहेगी, साथ ही मूल्य स्थिरता बनाई रखी जायेगी। लोक वित्त के संबंध में सरकार पर आकस्मिक राजकोषीय दबाव अपेक्षाकृत कम है क्योंकि सरकार के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए बकाया गारंटियां कम हैं। तथापि, लोक वित्त उच्चतर बाह्य और गैर-बैंकिंग वित्तपोषण के होते हुए भी कार्यान्वयन क्षमता के अवरोधों के कारण खर्च में कटौती से प्रभावित होंगे। वर्ष 2009-10 के लिए अनुमानित बजट घाटा जीडीपी का 4.5% रखा गया है जबकि अनुमानित स्तर 5.0% था। विकास कार्यक्रम परियोजनाओं का कुशल और शीघ्र कार्यान्वयन निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने की स्थिति पैदा कर सकते हैं और मौद्रिक नीति के साथ व्यापक, समावेशी और पर्यावरण की दृष्टि से व्यवहार्य विकास के लिए सहायता प्रदान कर सकते हैं।

भूटान

33. भूटान का आर्थिक कार्यनिष्पादन राजनैतिक स्थिरता और विवेकपूर्ण आर्थिक नीतियों के सहारे हाल में सुदृढ़ रहा है। देश अपने सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर भलीभांति अग्रसर है और इसने दसवीं पंचवर्षीय योजना (2008-13) में विभिन्न प्रकार की

विकास कार्य-सूची को रेखांकित किया है। वित्तीय संकट का प्रभाव बहुत सीमित और केवल पर्यटन क्षेत्र तक सीमित रहा। पुनात्संगछु-1 और मंगडेछु जलबिजली परियोजनाओं के सहारे पूरी मध्यावधि में विकास 7% के आसपास रहने की संभावना है। वर्ष 2009 में औसत मुद्रास्फीति कम अर्थात् 4% रही, लेकिन भारत में मुद्रास्फीति के घटनाक्रम के बाद वर्ष 2010 की पहली तिमाही में मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2008-09 में सरकारी राजस्व और खर्च दोनों में अत्यधिक वृद्धि हुई, राजस्व में वृद्धि जीडीपी के 33% से बढ़कर 39% और खर्च 33% से बढ़कर 41% हो गया। बाह्य क्षेत्र में परिवर्तनीय मुद्रा भंडार उच्च बना रहा, जबकि रुपया भंडार में हाल के महीनों में अत्यधिक वृद्धि हुई। वित्तीय क्षेत्र में ऋण वृद्धि अभी भी अच्छी है लेकिन निजी क्षेत्र में कम हो रही है। वित्तीय क्षेत्र में उदारीकरण नीति का मुख्य ध्यान इस क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और कार्यकुशलता पर है, निजी क्षेत्र के तीन और बैंकों को लाइसेंस प्रदान किया गया है और निजी क्षेत्र की चुनिंदा संस्थाओं को बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति प्रदान की गई।

समापन टिप्पणी

34. उन्नत और उभरते एवं विकासशील, दोनों प्रकार के देशों द्वारा ठोस और निर्णायक कार्रवाइयों ने अभूतपूर्व

वित्तीय और आर्थिक संकट का सामना करने के लिए दुनिया की सहायता की। हमारी प्रतिक्रिया ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ किया है और यह विश्वास जगाया कि हम साथ मिलकर दुनिया की वित्तीय स्थिरता की सुरक्षा कर सकते हैं और धारणीय आर्थिक विकास हासिल कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए अनेक उल्लेखनीय और ठोस कदम उठाये गये हैं, महत्वपूर्ण कदमों में से एक कोष को पर्याप्त रूप से मजबूत करना है जिसमें इसकी निगरानी में सुधार, संसाधनों का विस्तार और ऋण सुविधाओं में सुधार शामिल हैं। आगे चल कर कोष भविष्य के संकटों के बारे में चेतावनी देने, स्थिरता को संभावित चुनौती से अपने सदस्यों की रक्षा को मजबूत करने, उनके हड़ताल पर जाने से उत्पन्न संकट से होने वाली कठिनाइयों को न्यूनतम करने और सामान्यतः सुदृढ़ और धारणीय विकास के लिए अनुकूल वैश्विक वातावरण तैयार करने में मुख्य भूमिका निभानी होगी। इसके लिए कोष को अपनी भूमिका और अधिदेश को नया आकार और पुनर्निर्धारित करना होगा, ताकि यह बदलते समय की अपेक्षाओं के अनुरूप हो सके। कोष के नये रूपरंग के लिए काफी कुछ हासिल कर लिया गया है, लेकिन काफी और करने की जरूरत है, विशेषकर संगठन और अभिशासन के क्षेत्र में सुधार करने हैं जिनको स्वीकार्यता, वैधता और स्वायतता से संपन्न रूप में परिकल्पित किया जा रहा है।